नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 076
दि. 18.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

परमाणु ऊर्जा के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खुले लोकसभा से पारित 'शांति' विधेयक पर सियासी संग्राम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक और दूरगामी बदलाव की नींव रखते हुए लोकसभा ने बुधवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता साफ करने वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए सरकार ने न केवल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, शोध और पर्यावरण जैसे गैर-विद्युत क्षेत्रों में भी इसके उपयोग को विस्तार देने का संकेत दिया है। हालांकि, इस फैसले को जहां सरकार भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जन सुरक्षा और पर्यावरण के लिए जोखिम भरा करार दे रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 'सतत दोहन और भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन विधेयक, 2025', जिसे संक्षेप में 'शांति विधेयक' कहा जा रहा है, को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। लंबी चर्चा के बाद जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा कानूनों का आधुनिकीकरण करना और इस क्षेत्र को अधिक समावेशी बनाना है। उनका कहना था कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए अब केवल सरकारी संसाधनों के भरोसे आगे बढ़ना पर्याप्त नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी हो गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से कोई नया कानून नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों में समय की मांग के अनुसार आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक की एक अहम धारा निजी व्यक्तियों और

संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार की अनुमति देती है, ताकि भारत इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके। साथ ही सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी कंपनी या इकाई की भागीदारी को प्रतिबंधित कर सके। मंत्री ने जोर देकर कहा कि विधेयक में सुरक्षा, संरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, परमाणु दायित्व और आपातकालीन तैयारियों से जुड़े प्रावधानों को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। विपक्ष के विरोध पर पलटवार करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कई विपक्षी सदस्य विधेयक को पूरी तरह पढ़े बिना ही उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्तापक्ष का विरोध करने के चक्कर में विपक्षी सांसद अपने ही कार्यकाल के दौरान बनाए गए कानूनों और प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक, सरकार का लक्ष्य किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं, बल्कि नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे देश को ऊर्जा सुरक्षा मिल सके। सरकार ने सदन को बताया कि इस विधेयक के लागू होने के बाद परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान नया अधिनियम लेगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करना, साथ ही छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की बड़े पैमाने पर तैनाती को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि तकनीकी नवाचार, रोजगार और शोध के नए अवसर भी पैदा होंगे।

हालांकि, विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इस विधेयक को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ उठाया गया एक खतरनाक कदम बताया। लोकसभा में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि पैसों की लालसा को जन सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पीड़ितों को न्याय की जरूरत पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। उनका आरोप था कि प्रस्तावित कानून अपवादों से भरा हुआ है, इसमें अत्यधिक विवेकाधिकार दिए गए हैं और यह जनकल्याण के प्रति संवेदनशील नहीं दिखता। शशि थरूर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह वास्तव में एक परमाणु विधेयक है या फिर एक अस्पष्ट और भ्रम पैदा करने वाला कानून। उन्होंने चेतावनी दी कि यह विधेयक निजीकृत परमाणु विस्तार की दिशा में एक ऐसा कदम है, जो भविष्य में गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि 'शांति' शब्द का अर्थ शांति और स्थिरता होता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि यह नाम किसी रोकी जा सकने वाली आपदा के बाद एक क्रूर विडंबना न बन जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को बदलने के वादे को भारत को कलंकित करने के जोखिम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया कि प्रस्तावित कानून अंतरराष्ट्रीय परमाणु दायित्व मानकों, सुरक्षा उपायों और नियामक ढांचे के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को कमजोर नहीं करेगा। विधेयक का उद्देश्य सुरक्षित उपयोग के साथ-साथ जनकल्याण सुनिश्चित करना बताया गया है। अब इस विधेयक के पारित होने के बाद निगाहें इस पर टिकी हैं कि निजी क्षेत्र की एंट्री से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी तेजी से बढ़ती है और क्या सरकार सुरक्षा और पारदर्शिता के अपने दावों पर खरी उतर पाती है या नहीं।

बंगाल की खाड़ी में भारत की बड़ी सैन्य तैयारी, विशाखापत्तनम तट के पास 3240 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल परीक्षण संभव

(जीएनएस)। विशाखापत्तनम। भारत अपनी सामरिक ताकत को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी मिसाइलों और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण की गति लगातार तेज हुई है। इसी कड़ी में अब बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर बड़ी सैन्य गतिविधि के संकेत मिले हैं। भारत सरकार की ओर से विशाखापत्तनम तट के पास 22 से 24 दिसंबर की अवधि के लिए NOTAM यानी नोटिस टू एयरमेन जारी किया गया है, जिसे रक्षा विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण से जोड़कर देख रहे हैं। जारी किए गए NOTAM के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा समुद्री क्षेत्र अस्थायी रूप से हवाई यातायात के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचित क्षेत्र की अनुमानित रेंज लगभग 3,240 किलोमीटर बताई जा रही है, जो इसे एक लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण गतिविधि की ओर

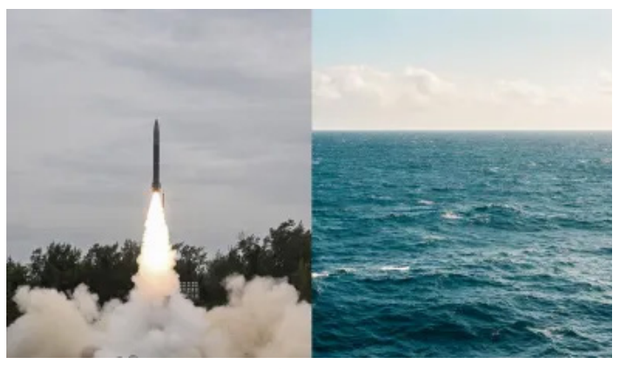

इशारा करने वाला बनाती है। आमतौर पर इतनी बड़ी रेंज वाले NOTAM तब जारी किए जाते हैं, जब किसी बैलिस्टिक या एडवांस्ड स्ट्रैटेजिक मिसाइल के परीक्षण की योजना होती है, ताकि हवाई और समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रक्षा सूत्रों के अनुसार, विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी पहले भी भारत के कई अहम मिसाइल परीक्षणों का साक्षी रहा है। यहीं से अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों सहित कई समुद्र आधारित और लंबी दूरी की प्रणालियों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस बार जारी NOTAM को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि परीक्षण किसी ऐसी मिसाइल से जुड़ा हो सकता है, जिसकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक है और जो भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करेगी।

हालांकि, सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक किसी भी मिसाइल प्रणाली या प्लेटफॉर्म को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार परख रहा है और आधुनिक तकनीक से लैस हथियार प्रणालियों को operational readiness में लाने पर जोर दे रहा है। समुद्र आधारित परीक्षणों का उद्देश्य खास तौर पर भारत की दूसरी मारक क्षमता यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना भी माना जाता है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइलें न केवल भारतीय सेनाओं की ताकत बढ़ा रही हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में जारी यह NOTAM एक बार फिर इस बात का संकेत है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और आने वाले दिनों में देश की सैन्य शक्ति का एक और प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।

चलती बसों में जलती जिंदगियां, तीन साल में आग की 45 घटनाओं ने लीं 64 जानें, संसद में सामने आई डराने वाली तस्वीर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक तस्वीर बुधवार को संसद में सामने आई, जब केंद्र सरकार ने खुलासा किया कि बीते तीन वर्षों में बसों में आग लगने की 45 घटनाओं में 64 लोगों की जान चली गई। ये घटनाएं ऑपरेशन के दौरान हुईं और 10 दिसंबर तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, इन हादसों में सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में दर्ज की गई हैं, जहां बस में आग लगने की घटनाओं में कम से कम 45 लोगों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही मौतों के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर रहा, लेकिन बसों में आग लगने की घटनाओं की संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक दर्ज की गई। महाराष्ट्र में तीन साल की अवधि में ऐसी नौ घटनाएं सामने आईं। इसके बाद मध्य प्रदेश में आठ घटनाएं हुईं। राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसी अवधि में छह-छह घटनाएं दर्ज की गईं, जो यह संकेत

देती हैं कि यह समस्या केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में यात्रियों की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद नारायण दास गुप्ता के सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में हाल की एक बेहद भयावह दुर्घटना शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक बस की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बस में आग लग गई और इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के शामिल न होने के बावजूद आंकड़े यह दिखाने के लिए काफी हैं कि बसों में आग लगने की घटनाएं कितनी घातक साबित हो रही हैं।

सरकार ने संसद को यह भी बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मंत्रालय ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2016 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 119 के तहत नियमों में बदलाव किए थे, जिनका उद्देश्य बसों में आग जैसी आपात स्थितियों से निपटना था। इन संशोधनों के तहत अब बसों में कुल 10 किलोग्राम क्षमता वाले दो अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। इनमें से एक अग्निशामक ड्राइवर के पास और दूसरा यात्री कक्ष में रखा जाना जरूरी है।

इसके अलावा, सुरक्षा मानकों के तहत 12 मीटर तक लंबी बसों में चार आपात निकास द्वार और उससे अधिक लंबाई वाली बसों में एक अतिरिक्त एग्जिट का प्रावधान किया गया है। इंजन में फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम लगाने की व्यवस्था भी नियमों का हिस्सा है, ताकि आग लगते ही उसे नियंत्रित किया जा सके। साथ ही, सभी प्रकार की बसों में ड्राइवर और यात्री कक्ष के बीच किसी तरह का स्थायी बंटवारा न रखने का प्रावधान किया गया है, ताकि आपात स्थिति में आवाजाही और बचाव कार्य में बाधा न आए।

संसद में सामने आए ये आंकड़े और विवरण यह साफ संकेत देते हैं कि नियमों और तकनीकी उपायों के बावजूद बसों में आग लगने की घटनाएं पूरी तरह थमी नहीं हैं। ऐसे हादसे न केवल यात्रियों की जान लेते हैं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को भी झकझोरते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन हो रहा है और क्या राज्यों के स्तर पर निगरानी और जवाबदेही को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि चलती बसों में जलती जिंदगियों का यह सिलसिला थम सके।

रेलवे में सुरक्षा की मजबूत निगरानी, देशभर के 1,731 स्टेशनों और करीब 12 हजार कोचों में सीसीटीवी से रखी जा रही पैनी नजर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में रेल मंत्रालय ने संसद को बताया है कि देशभर में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के कोचों में सीसीटीवी कैमरों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। अब तक देश के 1,731 रेलवे स्टेशनों और 11,953 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे रेलवे परिसरों में होने वाली गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, यह पूरा काम कैपिटल खर्च के तहत किया गया है और इसका उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी नेटवर्क के विस्तार से न सिर्फ चोरी, छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिली है, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी संभव हो पाई है। कैमरों की मदद से रेलवे सुरक्षा बल और संबंधित एजेंसियां भीड़ प्रबंधन, महिला सुरक्षा और प्लेटफॉर्म व ट्रेनों में होने वाली घटनाओं की प्रभावी निगरानी कर पा रही हैं।

देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार अपग्रेड किया गया है। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट, फुट ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और टिकट काउंटर जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पहले से ही बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसके अलावा 15 फरवरी 2025 के बाद स्टेशन परिसर में विकसित किए गए नए क्षेत्रों को भी निगरानी के दायरे में लाने के लिए अतिरिक्त कैमरे स्थापित किए गए हैं। मौजूदा समय में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुल 250 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय हैं, जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। रेल मंत्रालय का कहना है कि आने वाले समय में भी यह अभियान जारी रहेगा और चरणबद्ध तरीके से और अधिक स्टेशनों व कोचों को सीसीटीवी निगरानी से जोड़ा जाएगा। मंत्रालय का मानना है कि तकनीक के इस व्यापक उपयोग से रेलवे में यात्रियों का भरोसा और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगे और किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम में यह व्यवस्था निर्णायक भूमिका निभाएगी।

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में तेज हुई सियासी सरगर्मी, पुणे से नागपुर और संभाजीनगर तक दलों की रणनीति ने पकड़ी रफ्तार

(जीएनएस)। पुणे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पुणे से लेकर नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर तक सभी प्रमुख दल मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने पुणे महानगरपालिका चुनाव में औपचारिक रूप से अपनी एंट्री कर दी है। पार्टी ने चुनावी तैयारी को मजबूत संकेत देते हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और साफ कर दिया है कि वह इस बार किसी भी बड़े शहर को खाली छोड़ने के मूड में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए प्रभागवार 25 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि पुणे महानगरपालिका की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहली सूची में प्रभाग 3 (अ) से शितल कांडेलकर, प्रभाग 5 (अ) से संतोश काले, प्रभाग 6 (अ) से श्रद्धा शेट्टी और प्रभाग 7 (ड) से शंकर थोरात को टिकट दिया गया है। पार्टी का कहना है कि वह स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार और नागरिक सुविधाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी और पुणे की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पेश करेगी। दूसरी ओर नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। नागपुर महानगरपालिका चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन टिकट के दावेदारों की भारी भीड़ के चलते पार्टी कार्यालय में अव्यवस्था की स्थिति बन गई। मंगलवार से शुरू हुए साक्षात्कार के पहले ही दिन बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवार पहुंच गए, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालात को संभालने के लिए पार्टी को साक्षात्कार कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा।

भाजपा नेतृत्व ने अब साक्षात्कार की अवधि बढ़ाते हुए इसे 18 दिसंबर के बजाय 20 दिसंबर तक करने का फैसला किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के दावेदारों के साक्षात्कार तय तिथियों में लिए जाएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नागपुर महानगरपालिका चुनाव के लिए तीन हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर टिकट पाने की होड़ कितनी तेज है। कई दावेदारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन नेतृत्व का कहना है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को अवसर देने के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा रहा है।

इसी बीच छत्रपति संभाजीनगर में भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आगामी 15 जनवरी को होने वाले महानगरपालिका चुनाव को देखते हुए दोनों दलों के नेता बंद कमरे में लगातार बैठकें कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे यह साफ है कि दोनों दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे को लेकर गहन मंथन चल रहा है और यह तय करने की कोशिश हो रही है कि किस दल को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। साक्षात्कार के जरिए उम्मीदवारों की जनसंपर्क क्षमता, संगठनात्मक मजबूती और स्थानीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। संभाजीनगर की राजनीति में भाजपा और शिवसेना के बीच तालमेल को लेकर चर्चाएं तेज हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों से पहले राज्य के प्रमुख शहरों में राजनीतिक दलों की सक्रियता चरम पर पहुंच गई है और आने वाले हफ्तों में यह मुकाबला और रोचक होने की उम्मीद है।

संपादकीय

जीवन शैली में बदलाव से ही समाधान

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घातक पर्यावरण संकट झेल रही है। विडंबना यह है कि इस संकट के निदान के लिये जो उपाय लागू किए जा रहे हैं, उसका खमियाजा गरीबों को झेलना पड़ रहा है। इस संकट की संवेदनशीलता को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमीरों की जीवन शैली से उपजी मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। दरअसल, बिगड़ते प्रदूषण संकट के बाबत दायर याचिकाओं को आज सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह मर्मस्पर्शी टिप्पणी की। कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि वह इस बाबत प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश पारित करेगा। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ वकील और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए ये टिप्पणी की थी। अदालत का कहना था कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-4 लागू करने के चलते जो पाबंदियां लागू की गई हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को हो रहा है। इससे निर्माण कार्य बंद होने से हजारों गरीब मजदूरों का चूल्हा नहीं जल सकेगा। मुख्य न्यायाधीश ने इस बाबत कहा कि संपन्न लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही कहा कि हमें समस्या का पता है और इसलिए हम ऐसे आदेश पारित करेंगे, जिनका पालन किया जा सकेगा। कहा कि कुछ निर्देश ऐसे भी हैं, जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि महानगरों में लोगों की अपनी अलग जीवनशैली होती है, जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि समस्या अमीरी की वजह से होती है, लेकिन झेलना गरीब को पड़ता है। दरअसल, अदालत की सोच रही है कि हमारा परिवेश-पर्यावरण साफ-सुथरा रहे, इसके लिये हम सबको अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा। यह जानते हुए कि पर्यावरण पर आने वाले संकट व प्रदूषित हवा का अमीर-गरीब पर समान असर पड़ता है।

निस्संदेह, देश की शीर्ष अदालत ने देश व समाज की दुखती रग पर ही हाथ रखा है। महानगरों में अमीर तबके की विलासिता के चलते ही पर्यावरण व अन्य संकटों को बढ़ावा मिलता है। महानगरों में लगातार सड़कों का विस्तारीकरण, नए हाइवे निर्माण व ओवर ब्रिज निर्माण के बावजूद जाम व प्रदूषण का संकट कम नहीं हो रहा है। दरअसल, हमने अपनी सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन व्यापक सामाजिक हितों की अनदेखी की है। आमतौर पर एक अकेले व्यक्ति के लिये कारें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। जो न केवल सड़कों में ज्यादा जगह घेरती हैं, बल्कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके प्रदूषण को भी बढ़ावा देती हैं। यही वजह है कि आम आदमी सरकार ने अपने कार्यकाल में ऑड-इवन प्रणाली शुरू करने को प्राथमिकता दी थी ताकि सड़कों पर कारों का सैलाब कम किया जा सके। तब बात उठी थी कि एक दिशा में और एक ऑफिस की तरफ जाने वाले लोग कार शेयर करके चलें। विडंबना यह है कि सत्ताधीशों ने दिल्ली में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने को प्राथमिकता नहीं दी। यदि सार्वजनिक परिवहन सस्ता व सहज उपलब्ध होता तो शायद सड़कों पर कारों का दबाव कम होता। हाल के दिनों में संपन्न व मध्यम वर्ग में एसी व अन्य वातानुकूलन उपायों के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इससे जहां प्रदूषण बढ़ाने वाली बिजली की खपत बढ़ी है, वहीं बाहर का तापमान व कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है। इसी तरह तमाम अमीरों द्वारा संचालित उद्योगों में उन उपायों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया जो पर्यावरण में प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। विडंबना यह है कि महानगरों व अन्य शहरों में जहां कुछ इलाकों में पेयजल का संकट बना रहता है, वहीं दूसरे पॉश इलाकों मे लॉन सींचने, कार धोने और स्वीमिंग पूलों के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। अकसर कहा जाता है कि कुदरत ने हर व्यक्ति के लिए हवा, पानी व भोजन उपलब्ध कराया है, लेकिन इनके असमान वितरण व अमीरी के दखल के चलते, गरीब के साथ न्याय नहीं हो पाता है। अमीर होना बुरा नहीं है लेकिन उसकी अमीरी की कीमत गरीब को न चुकानी पड़े।

वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम आदेश, निर्णय केंद्र करे

> “ये एक जगह नही है, श्रद्धालु को इस समस्या से अधिकांश जगह रूबरू होना पड़ता है। जगह–जगह मंदिरों में इस समस्या का सामना होता है। लगभग 40 साल पहले हम कोलकत्ता गए। कालिका जी मंदिर में हम श्रद्धालुओं की लाइन में लगे थे कि हमारे एक साथी ने देखा और हमें इशारा कर अपने पास बुला लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में ‘वीआईपी दर्शन’ सुविधा को चुनौती देने वाली याचिका भले ही खारिज कर दी, किंतु इस याचिका पर कोर्ट द्वारा कही गई बातों की गूंज दूर तक जाएगी। यह गूंज केंद्र सरकार को विवश करेगी कि वह मंदिरों में हाने वाले वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाने वाला निर्णय लें। कोर्ट की ये गूंज आने वाले समय में मंदिरों के वीवीआईपी दर्शन कर रोक लगाने का रास्ता प्रशस्त करेगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि वीआईपी के लिए ऐसा विशेष व्यवहार मनमाना है। यह याचिका मंदिरों की तरफ से वसूले जाने वाले वीआईपी दर्शन शुल्क को समाप्त करने की मांग कर रही थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेंच इस मुद्दे से सहमत है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, ‘हालांकि हमारी राय है कि मंदिरों में प्रवेश के संबंध में कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का उपयुक्त मामला है।’ यह आदेश में दर्ज किया गया लेकिन मामला सरकार के विचार के लिए छोड़ दिया गया। पूर्व CJI खन्ना ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था का प्रतीत होता है और याचिका इस पहलू पर होनी चाहिए थी। बेंच ने कहा, ‘हम स्पष्ट करते हैं कि याचिका खारिज होने से संबंधित अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ‘आज 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ इस

प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ये मनमाना और भेदभाव वाला है। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने भी आंध्र प्रदेश से इसकी समीक्षा करने को कहा है। चूंकि, भारत में 60 प्रतिशत पर्यटन धार्मिक है, इसलिए ये भगदड़ की प्रमुख वजह भी है।’ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका विजय किशोर गोस्वामी ने डाली थी। उन्होंने मंदिरों में अतिरिक्त शुल्क लेकर ‘वीआईपी दर्शन’ के चलन को आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार और आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने दलील दी कि जो लोग इस तरह का शुल्क अदा करने में असमर्थ हैं, ये उनके खिलाफ भेदभाव है। याचिका में जोर देकर कहा गया था कि कई मंदिर 400 से 500 रुपये में लोगों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था करते हैं। इससे आम श्रद्धालु और खासकर महिलाएं, स्पेशली एबल्ड लोग और सीनियर सिटिजंस को दर्शन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह मामला देश भर के मंदिरों में आम लोगों और वीआईपी के बीच भेदभाव के मुद्दे को उठाता है। वीआईपी दर्शन की सुविधा से आम लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, जबकि वीआईपी आसानी से दर्शन कर लेते हैं। ये एक जगह नही है, श्रद्धालु को इस समस्या से अधिकांश जगह रूबरू होना पड़ता है। जगह–जगह मंदिरों में इस समस्या का सामना होता है। लगभग 40 साल पहले हम कोलकाता गए। कालिका जी मंदिर में हम श्रद्धालुओं की लाइन में लगे थे कि हमारे एक साथी ने देखा और हमें इशारा कर अपने पास बुला लिया। यहां पुजारी पांच रूपया प्रति व्यक्ति लेकर सीधे दर्शन करा रहे थे। अभी वेट द्वारिका जाना हुआ। हम परिवार के छह सदस्य थे। एक पंडित जी ने हमसे पांच सौ रूपये लिए। अलग लाइन से हमें आराम से दर्शन कराए। भीड़भाड़ भी बची। वैसे दर्शन में दो से तीन घंटे लगते पांच सौ रूपये में आधा घंटा में दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गए। करीब दस साल पहले हम गुजरात में अम्बा जी गए थे। दर्शन की लाइन में लगे थे कि कर्मचारियों ने यह कह कर हमके रोक दिया कि दर्शन का समय समाप्त हो गया, जबकि कुछ अन्य को लगातार प्रदेश दिया जा रहा। किसी तरह हम अन्यों वाली पंक्ति में शामिल हुए। तब दर्शन हुए। दर्शन भी बड़े आराम से हुए। काफी समय हम मंदिर में रूके, जबकि ऐसा पहले संभव नही था। इस तरह का भेदभाव हमें कई जगह देखने को मिला। उज्जैन में तो आप पंडित को पांच सौ के आसपास रूपये दीजिए। वह मंदिर के गर्भ गृह में ले जाकर पूजन अर्चन कराते हैं। जो ये रकम नही देते वे गर्भगृह के बाहर ही दूर से दर्शन कर तृप्त हो जाते हैं। ओंकारेश्वर में तो पंडित जी पूजा भी आराम से और श्रद्धालुओं की पंक्ति से अलग लेकर कराते हैं। मथुरा जी के बांके बिहारी मंदिर में सुप्रीम आदेश से यह व्यवस्था रूकी है, अन्यथा लगभग सभी मंदिरों की हालत ऐसी ही है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, किंतु इस वीआईपी दर्शन पर रोक वाली गेंद केंद्र सरकार के पाले में यह कह कर डाल दी। बेंच ने कहा कि बेंच इस मुद्दे से सहमत है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि वीआईपी के लिए ऐसा विशेष व्यवहार मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अब केंद्र सरकार को विवश करेगा कि मंदिरों में आम आदमी के साथ हो रहे भेदभाव को रोके और बांके बिहारी मंदिर की तरह पैसा लेकर कराए जा रहे वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म करे। व्यवस्था अयोध्या जी के श्रीराम मंदिर जैसी हो, जहां श्रद्धालु बिना भेदभाव आराम से 2530 मिनट में दर्शन कर बाहर आ सके।

प्रेरणा

जब 96 की उम्र में खुली अक्षरों की दुनिया

कार्तियानी अम्मा की कहानी उस साहस और जिद की मिसाल है, जो उम्र, हालात और सामाजिक सीमाओं को चुनौती देती है। उनका जीवन उन लाखों महिलाओं जैसा ही था, जिनकी पूरी ज़िंदगी परिवार की जिम्मेदारियों में बीत जाती है। बचपन से ही घर–गृहस्थी, बच्चों की परवरिश और रोज़मर्रा के संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा रहे। पढ़ाई का सपना कहीं मन के भीतर दबा रह गया, क्योंकि उस दौर में परिवार और परिस्थितियाँ ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थीं।

समय के साथ उम्र बढ़ती गई, लेकिन मन में कहीं न कहीं यह एहसास बना रहा कि पढ़ना-लिखना कितना ज़रूरी है। शब्दों को समझ पाने की इच्छा, कागज़ पर अपने विचार उतारने का सपना कभी पूरी तरह बुझा नहीं। यही वजह थी कि जब एक दिन उनकी बेटी अमिनी अम्मा ने उन्हें पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया, तो कार्तियानी अम्मा ने उस सुझाव को उम्र का मज़ाक मानकर ठुकराया नहीं, बल्कि उसे जीवन का नया अवसर समझ लिया। बेटी का विश्वास मां के भीतर छिपे आत्मविश्वास को जगा गया।

इसके बाद उन्होंने केरल राज्य साक्षरता मिशन अथॉरिटी द्वारा आयोजित ‘अक्षरलक्ष्यम’ साक्षरता परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया। यह परीक्षा उन लोगों के लिए होती है, जिन्हें बचपन में कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसमें पढ़ना, लिखना और गणित की बुनियादी समझ सिखाई जाती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी काले अक्षरों को सफेद कागज़ पर नहीं उकेरा हो, उसके लिए इस उम्र में सीखना आसान नहीं होता। आंखें जल्दी थक जाती हैं, याददाश्त साथ नहीं देती और हाथों की पकड़ कमजोर हो जाती है।

इन सभी कठिनाइयों के बावजूद कार्तियानी अम्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की। हर अक्षर उनके लिए नई पहचान था, हर संख्या एक नई उपलब्धि। धीरे-धीरे वे उस दुनिया में कदम रखने लगीं, जिससे वे दशकों तक दूर रहीं। यह केवल परीक्षा की तैयारी नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने की यात्रा थी। वे यह साबित करना चाहती थीं कि सीखने की चाह अगर सच्ची हो, तो उम्र कभी दीवार नहीं बनती।

जब परीक्षा का परिणाम सामने आया, तो यह खबर सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। 96 वर्ष की उम्र में कार्तियानी अम्मा ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि 100 में से 98 अंक हासिल कर सबसे अधिक अंक पाने वालों में शामिल हो गईं। यह उपलब्धि उन सभी धारणाओं को तोड़ने वाली थी, जो यह मानती हैं कि सीखने का समय केवल बचपन या जवानी तक ही सीमित होता है।

उनके शिक्षा के प्रति इस जुनून ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। वर्ष 2019 में उन्हें कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का गुडविल एंबेसडर नियुक्त किया गया, जिससे वे दुनिया भर में शिक्षा और साक्षरता की प्रेरक प्रतीक बन गईं। इसके बाद वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके संघर्ष, समर्पण और उस सोच के लिए था, जिसने समाज को नई दिशा दी।

कार्तियानी अम्मा ने 95 वर्ष की उम्र पार करने के बाद शिक्षा हासिल कर यह सिद्ध कर दिया कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उन्होंने उन लोगों को आईना दिखाया, जो थोड़ी-सी असफलता या उम्र का बहाना बनाकर सीखना छोड़ देते हैं। वर्ष 2023 में उनका निधन हो गया। आज वे हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है, जो यह सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कार्तियानी अम्मा यह अमिट संदेश छोड़ गईं कि सीखने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है—बस हिम्मत और जुनून ज़िंदा रहना चाहिए।

मानसिकता और कार्यक्षमता को प्रभावित करती वर्चुअल मीटिंग्स

डिजिटल क्रांति ने कार्यदिवस के परंपरागत समय सीमा को बदलकर ही रख दिया है। कहने को तो छह या सात घंटे का कार्यदिवस होता है पर वर्चुअल युग में कर्मचारी 24 गुणा 7 के दौर में आ गया है। इससे कार्मिकों की मानसिकता और सामाजिक-इकोनोमिक ताने-बाने को भी प्रभावित किया है। एक समय था जब शीर्ष या पहली दूसरी कतार के अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक होती थी और उनके लिए समय सीमा नहीं होती थी पर अब तो वर्चुअल सुविधाओं के चलते दिन हो या रात रविवार हो या शनिवार कभी भी कहीं भी एक मैसेज मात्र से आपको एक्टिव होकर कैमरे के सामने आना पड़ता है। दरअसल कोरोना काल ने यह परिवर्तन दिया है। भारत सहित दुनिया के देशों में अभी भी कार्मिकों के लिए कार्यदिवस पांच या छह दिवस के हैं तो कार्यसमय भी मानने को तो सुबह 9.30 से सायं बजे 6 या दूसरे शब्दों में औसतन लगभग सात घंटे का है पर डिजिटल क्रान्ति ने सबकुछ बदल कर रख दिया है। देखा जाए तो अब असीमित कार्य दिवस का दौर आ गया है। वास्तविकता तो यह है कि डिजिटल डिवाइसों के उपयोग के बाद से कमोबेस कार्यदिवस 24 गुणा 7 हो गये हैं तो कार्य समय भी तय समय सीमा के बंधन से मुक्त हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कराये गये वर्क ट्रेंड इंडेक्स स्पेशल रिपोर्ट 2025 में यह खुलासा हो गया है कि अब कार्मिक चाहे वह किसी भी स्तर का हो के लिए चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में तय समय सीमा बीते जमाने की बात हो गई है। ई-मेल, चैट, वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स, सोशल मीडिया संदेश आदि को समग्र रुप से देखने से अब कार्मिक 24 घंटे का कार्मिक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सुबह छह बजे से ही व्यक्ति अपनी ई-मेल अपना संदेश संबंधित सभी तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम होने के बावजूद यह तनाव का कारण तो बनता ही है इसके साथ ही गुणवत्ता पर भी प्रश्न लगाये जाने लगे हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि दस में से एक मीटिंग लास्ट टाइम बुक की जाती है तो मीटिंग्स में प्रस्तुत होने वाले पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन में मीटिंग के दस मिनट पहले तक आंषिक बदलाव या अपडेशन होता है। यह कोई किसी एक पक्ष यानी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान की बात या किसी देष विशेष की बात ना होकर वैश्विक वास्तविकता है। विशेषज्ञों की माने तो अंतिम समय तक प्रजेंटेशन में बदलाव का मतलब ही यह है कि गुणवत्ता कहीं ना कही प्रभावित हो रही है। वैश्विक आंकड़े तो यही कहते हैं कि अंतिम समय में पीपीटी में अपडेशन या संशोधन में 122 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला दरअसल कोरोना महामारी के दौर से अधिक सामने आया है और इसे समय और धन बचाने में सहायक माना जाता है पर मीटिंग्स के दौर जिस तरह से बढ़ने लगे हैं उससे कार्मिक सूचनाएं संग्रहित करने और उसमें अपने बचाव के उपाय खोजने में ही अपनी अधिकांश कार्यक्षमता व्यय कर देता है और परिणाम स्वरुप कार्य में गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आना स्वाभाविक माना जाने लगा है।

माइक्रोसॉफ्ट की हालिया रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि डिजिटल युग को देखते हुए अब कार्मिकों के कार्यदिवस को नए सिरे से रिडिजाइन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसका प्रमुख कारण कार्मिकों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना और सामाजिकता और वैयक्तितता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रमुख हो जाता है। समय बेसमय मोबाइल या इसी तरह की डिवाइस पर अंगुलियां चलाने से प्रभावित हो रहे हैं। काम का दबाव, सूचनाओं के संग्रहण में ही समय जाया होने, वर्चुअल मीटिंग्स में सार्वजनिक रुप से जलालत की संभावना, आंखों में सूखापन और सामाजिक व व्यक्तिगत संबंध बाधित होना आम होता जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट संत्रास, कुंठा, तनाव, डिप्रेशन आदि के रुप में सामने आने लगा है। इसके समाधान के लिए हांलाकि विशेषज्ञों ने फ्रंटियर फर्म की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इसमें आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस के माध्यम से विश्लेषण की बात की जाने लगी है। पर समय की मांग और आवश्यकता यह महसूस की जाने लगी है कि वर्क कल्चर को रिडिजाइन किया जाएं। अन्यथा देर सबेर इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल यह अपने आपमें गंभीर समस्या हो गई है। इसका समाधान हर स्तर पर खोजना होगा। यह कोई कार्यालयीय समस्या, सामाजिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या शारीरिक मानसिक समस्या ना होकर पूरे ताने-बाने को ही प्रभावित करने वाली समस्या है। ऐसे में विशेषज्ञों, गैरसरकारी संगठनों, मनोविज्ञानियों के साथ ही मानव संसाधन विशेषज्ञों और नियोक्ताओं को भी इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

अभियान

भाग्य, बुद्धि और विश्वास की डोर थामने का दिनः गुरुवार

मनुष्य का जीवन केवल कर्म से नहीं, बल्कि सही दिशा और सही समय से भी आकार लेता है। कई बार व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदार रहता है, फिर भी उसे वह सफलता नहीं मिलती जिसकी वह अपेक्षा करता है। रिश्तों में कड़वाहट बनी रहती है, विवाह में देरी होती है, संतान सुख में बाधा आती है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसे समय में अक्सर बृहस्पति ग्रह कमजोर या अशुभ अवस्था में होते हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और यही ग्रह जीवन में ज्ञान, धर्म, विवेक, भाग्य और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। जब गुरु संतुलित नहीं होते, तो जीवन की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है। ऐसे में गुरुवार का व्रत व्यक्ति के लिए सहारा, साधना और सुधार का मार्ग बन जाता है।

गुरुवार को बृहस्पति और ब्रह्मा तत्व से जोड़ा गया है। यह दिन केवल उपवास रखने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और संकल्प का दिन माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु छठे, सातवें, आठवें या दसवें भाव में स्थित होते हैं, उनके जीवन में संघर्ष और रुकावटें अधिक देखी जाती हैं। कई बार व्यक्ति बिना कारण मानसिक दबाव में रहता है और उसे अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पाता। धनु और मीन राशि के जातकों के लिए तो गुरु स्वयं स्वामी ग्रह होते हैं, इसलिए इनके जीवन में गुरुवार का विशेष महत्व माना गया है। नियमित रूप से इस दिन संयम और श्रद्धा रखने से उनके जीवन में स्थिरता आने लगती है।

जब गुरु शत्रु ग्रहों जैसे शुक्र या बुध के प्रभाव में आ जाते हैं या राहु के साथ युति बना लेते हैं, तब व्यक्ति की सोच भ्रमित हो जाती है। वह सही निर्णय लेने में चूक करता है और अपने ही बनाए रास्तों पर ठोकर खाता है। बृहस्पति यदि नीच अवस्था में हों या किसी कारण से कमजोर हो जाएं, तो भाग्य का साथ छूटने लगता है। शास्त्रों में माना गया है कि बृहस्पति चौथे भाव से सुख, पांचवें भाव से बुद्धि और संतान तथा नौवें भाव से भाग्य को नियंत्रित करते हैं। इसलिए जब गुरु मजबूत होते हैं, तो जीवन अपने आप संतुलन में आ जाता है।

विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, बार-बार रिश्तों का टूटना या संतान प्राप्ति में बाधा—इन सभी समस्याओं की जड़ में भी गुरु की कमजोरी मानी जाती है। ऐसे में गुरुवार का व्रत व्यक्ति के भीतर धैर्य, समझ और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसी प्रकार जिन लोगों की आयु रेखा

कमजोर होती है, जो बार-बार बीमारी, भय या असुरक्षा से घिरे रहते हैं, उनके लिए भी गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक होती है। बृहस्पति को दीर्घायु और जीवन रक्षा का कारक माना गया है, इसलिए गुरुवार की साधना जीवन को स्थिरता देती है।

गुरु केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की सोच को भी दिशा देते हैं। जब मानसिकता उथली हो जाती है, व्यक्ति केवल तात्कालिक लाभ के पीछे भागने लगता है और दूरगामी परिणामों को नजरअंदाज कर देता है, तब समझना चाहिए कि गुरु दुर्बल हो रहे हैं। गुरुवार का व्रत विवेक, संयम और दूरदर्शिता को पुनः जागृत करता है। यदि कुंडली में दशम भाव प्रभावित हो, पितृ दोष बन रहा हो या जीवन के हर मोड़ पर असफलता मिल रही हो, तो गुरुवार का कठिन व्रत एक मजबूत आध्यात्मिक सहारा बन सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी मनोकामना की सिद्धि के लिए कम से कम 11 गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। गुरुवार केवल भोजन त्यागने का दिन नहीं है। यह दिन आचरण सुधारने और आत्मशुद्धि का भी दिन है। इस दिन हल्दी, सफेद चंदन या गोरोचन का तिलक लगाना गुरु तत्व को सक्रिय करता है। बुरी आदतें छोड़ने के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि गुरुवार को लिया गया संकल्प लंबे समय तक निभता है। इस दिन किया गया प्रायश्चित मानसिक बोझ को कम करता है और अंतर्मन को शांति देता है। उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ माना गया है। शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, विवाह, प्रशासनिक निर्णय और संतान से जुड़े रचनात्मक कार्यों के लिए यह दिन विशेष फलदायी होता है।

गुरुवार को घर में धूप-दीप देना, विशेषकर गुग्गुल की धूप जलाना, वातावरण को शुद्ध करने के साथ-साथ मानसिक तनाव को भी कम करता है। मान्यता है कि इससे गृह कलह, अनिद्रा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह दिन पारलौकिक सहायता का भी माना जाता है, जिससे व्यक्ति को अदृश्य स्तर पर संबल मिलता है।

यदि किसी व्यक्ति का गुरु अत्यंत अशुभ हो, तो केवल व्रत ही नहीं, बल्कि जीवनशैली में भी परिवर्तन आवश्यक होता है। नित्य पीपल पर जल चढ़ाना, सत्य बोलना, पिता, दादा और गुरुजनों का सम्मान करना, पीली वस्तुओं का सेवन, पीतल के बर्तनों का उपयोग, तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी की गांठ रखना, सुबह-शाम कपूर जलाना और घर के वास्तु को गुरु तत्व के अनुसार संतुलित करना—ये सभी उपाय धीरे-धीरे जीवन की जड़ में बैठे दोषों को शांत करने लगते हैं।

गुरुवार का व्रत व्यक्ति को केवल धार्मिक नहीं बनाता, बल्कि उसे भीतर से मजबूत, स्थिर और विवेकशील बनाता है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तो रास्ते खुलते हैं, निर्णय सही दिशा में जाते हैं और जीवन में संतुलन लौट आता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं—जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी संतोष न मिले, तब गुरुवार को गुरु की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

52,400 आगंतुकों के साथ खिजड़िया ने मजबूत की गुजरात की इको-टूरिज्म पहचान

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में गुजरात की इकोलॉजिकल उत्कृष्टता के बेजोड़ उदाहरण के रूप में उभरेगा खिजड़िया पक्षी अभयारण्य

▸▸ रामसर साइट के दर्जे के साथ खिजड़िया अभयारण्य गुजरात के टिकाऊ विकास का जीवंत उदाहरण

(जीएनएस)। गांधीनगर : खिजड़िया पक्षी अभयारण्य ने वर्ष 2024-25 के दौरान 52,400 से अधिक सैलानियों को आकर्षित कर इको-टूरिज्म क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान को मजबूत किया है। राज्य में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तब यह अभयारण्य पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) उत्कृष्टता और टिकाऊ विकास के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बन रहा है। वीजीआरसी 2026 से पहले, जामनगर के निकट स्थित खिजड़िया रामसर स्थल गुजरात के महत्वपूर्ण पाकृतिक लैंडमार्क के रूप में उभरकर सामने आया है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र आज राज्य के अग्रणी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहां प्राकृतिक लैंडस्कैप, वन्यजीवन, तटीय सुंदरता, आध्यात्मिक स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम देखने को मिलता है। सफेद रण से लेकर सौराष्ट्र के तीर्थ स्थलों, समुद्र तट और अभयारण्यों तक की यात्रा पर्यटकों को विविधतापूर्ण और यादगार अनुभव देती है।

600 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला खिजड़िया पक्षी अभयारण्य मीठे और खारे पानी के दुर्लभ संगम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह अनोखा पारिस्थितिक तंत्र पक्षियों के लिए एक विविधतापूर्ण निवास उपलब्ध कराता है। गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान यहां 317 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 332 हो गई है, जो इस अभयारण्य की लगातार विकसित होती जैव विविधता का प्रमाण है।

इस पारिस्थितिक समृद्धि को 2022 में वैश्विक मान्यता मिली, जब खिजड़िया को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। राज्य सरकार यहां पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रही है, जिसमें वॉच टावर, वन-कुटीर, पक्षी निरीक्षण प्लेटफॉर्म, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेल्फी पॉइंट और जानकारी देने वाले साइन बोर्ड शामिल हैं।

अभयारण्य की मुख्य ताकत इसके विविधतापूर्ण और सुरक्षित आवास स्थल में है, जहां मीठे पानी का बहाव समुद्री ज्वार के साथ मिलता है, और तटबंधों एवं खंदकों के नेटवर्क से यह और भी समृद्ध हो जाता है, जो वन्यजीवों के लिए आदर्श माइक्रोहैबिटेट यानी सूक्ष्म आवास बनाते हैं। ये सुविधाएं खिजड़िया को भारत के सबसे जीवंत पक्षी स्थलों में से एक बनाती हैं। साथ ही, यह आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण के प्रति गुजरात के वैज्ञानिक और योजनाबद्ध दृष्टिकोण को भी मजबूत बनाती है।

राजकोट में 10, 11 और 12 जनवरी, 2026 के दौरान आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व तैयारी के समय में, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात के एकीकृत विकास मॉडल का स्वाभाविक उदाहरण बनकर उभर रहा है, जहां पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक विकास एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता कृषि, पर्यटन, जलवायु लचीलापन और टिकाऊ बुनियादी ढांचा जैसी राज्य की मुख्य पहलों की पूरक है, जिन पर वीजीआरसी के दौरान विशेष फोकस रहेगा।

खिजड़िया पक्षी अभयारण्य की यह सफलता गाथा गुजरात के 'सस्टेनेबिलिटी के साथ समृद्धि' के विजन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है और आगामी क्षेत्रीय जुड़ाव मंच के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर उभर रही है।

सकारात्मक बातों के जरिये जीवन को खुशनुमा बनायें - श्रीमती मंजू लोढ़ा

आकृति आर्ट फाउंडेशन द्वारा 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी का मुंबई में शुभारम्भ

(जीएनएस)। मुंबई, 17 दिसम्बर। सुप्रसिद्ध समाजसेवी, साहित्यकार और लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मंजू लोढ़ा ने कहा है कि हमारे आस-पास खुशियाँ देने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बिखरी रहती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि छोटी-छोटी बातों में उलझकर अपनी सोच को नकारात्मक बना लेते हैं। इसलिए अगर खुश रहना है, तो हमें सकारात्मक बातों के ज़रिये अपने जीवन को खुशनुमा बनाने की कला सीखनी चाहिये।

श्रीमती लोढ़ा मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 की शाम देश की प्रमुख सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक संस्था *"आकृति आर्ट फाउंडेशन"* द्वारा आयोजित 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रही थीं। उन्होंने इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए आकृति आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक डायरेक्टर मनमोहन जायसवाल और सभी प्रतिभागी चित्रकारों को हार्दिक बधाई दी तथा उनकी निरंतर सफलता के लिए अनंत शुभकामनाएँ प्रकट कीं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए सुप्रसिद्ध गीतकार तथा मीडिया एवं जनसम्पर्क सलाहकार गजानन महतपुरकर ने कहा कि चित्रकला सचमुच ईश्वर की सच्ची भक्ति है, जिसमें चित्रकार अपने अंतर्मन के भावों की सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। उन्होंने मनमोहक कला प्रदर्शनी के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी। आकृति आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक डायरेक्टर मनमोहन जायसवाल ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 18 वर्षों से कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। इसी क्रम में संस्था की 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मेकर चैम्बर्स की आर्ट गैलेरी में 16 से 21 दिसम्बर तक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूरोप से आये 35 प्रतिष्ठित कलाकार भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे जल्दी ही अपनी टीम के साथ सभी कलाकारों के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आसानी से दुनिया के किसी भी कोने तक कलाकारों की कृतियाँ पहुँचाई जा सकती हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ राजनेता अविनाश काम्बले, प्रमुख समाजसेवी एवं श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिमूर्ति विकास महंते, बजाज समूह की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हैड सुश्री सुरुचि महतपुरकर कोरे तथा ऑल स्टेट ग्रुप के चेयरमैन अजोयकांत रुइया सहित विभिन्न वक्ताओं ने प्रदर्शनी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी में सुविख्यात चित्रकार एम एफ हुसैन, जामिनी रॉय, एस एच राजा, सोहन कुमार, पूर्वा तेनानी, प्रियेश, प्रधन्या पंडित, अनीता गोयल, संजना रामचंदानी, वैशाली शाह, प्रवीण पांडे, निशा गांधी, सलोनी गुप्ता, शोभना मेहता, सुनामदिनी जयंत, राजवी गांधी, निराली मोदी, राखी संघवी, रितिका सिंह, शेखर बर्वे, नंदा पाठक, सुमेध उन्नावने मयूर श्रीवंधनकर, नवाब जहान, तानिया फटनानी, ध्यानज्योति निंबालकर, शिवानी धुरिया, प्रीति शाह, आरती चोरड़िया, रूपाली मिस्त्री और श्रुति सोमन की पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में बहुत से कला प्रेमी, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट तथा संगीत और साहित्य जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रारम्भ में श्री जायसवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। विभिन्न अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ इस भव्य प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो आगामी 21 दिसम्बर, 2025 तक रोज़ाना दोपहर 12 से रात्रि 8 बजे तक सभी कलाप्रेमी दर्शकों के निःशुल्क अवलोकनार्थ खुली रहेगी।

कांदिवली और बोरीवली के बीच छठी लाइन कमीशनिंग के संबंध में नॉन इंटर्लोकिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें होंगी प्रभावित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच छठी लाइन कमीशनिंग के संबंध में नॉन-इंटर्लोकिंग कार्य हेतु 20 दिसंबर 2025 से 30 दिन का ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी।जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

आंशिक निरस्त ट्रेनें:-

▸▸ ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद-बोरीवली एक्सप्रेस 19 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और वसई रोड एवं बोरीवली के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली-अहमदाबाद एक्सप्रेस 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी और वसई रोड एवं बोरीवली के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल ट्रेनें

▸▸ ट्रेन संख्या 12902 अहमदाबाद-दादर गुजरात मेल अहमदाबाद से 27 दिसंबर 2025 को 01 घंटा, 10 एवं 15 जनवरी 2026 को 45 मिनट तथा 16 जनवरी 2026 को 30 मिनट रिशेड्यूल होगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से 28 दिसंबर 2025 को 01 घंटा 35 मिनट, 11 जनवरी 2026 को 30 मिनट, 16 एवं 17 जनवरी 2026 को 50 मिनट रिशेड्यूल होगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस 28 दिसंबर 2025 को मुंबई सेंट्रल से 01.00 घंटा रिशेड्यूल होगी।

बोरीवली स्टेशन ठहराव नहीं करने वाली ट्रेनें

▸▸ ट्रेन संख्या 22928 अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस लोकशक्ति एक्सप्रेस 27 दिसंबर 2025 को बोरीवली स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इस दौरान यह ट्रेन वसई रोड और अंधेरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा 45-50 मिनट विलंब से पहुंचेगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल 27 दिसंबर 2025 को बोरीवली स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इस दौरान यह ट्रेन वसई रोड और अंधेरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा 45-50 मिनट विलंब से पहुंचेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

दिल्ली चुनाव में प्रचार की जंग में कांग्रेस आगे, खर्च में बीजेपी को छोड़ा पीछे, नतीजों में फिर भी खाली हाथ

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में नतीजों के साथ-साथ चुनावी खर्च को लेकर भी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने इस बार पार्टी प्रचार और सोशल मीडिया कैंपेन पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पैसा खर्च किया, हालांकि उम्मीदवारों पर खर्च के मामले में वह पीछे रही। हैरानी की बात यह रही कि भारी खर्च के बावजूद कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जबकि भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा जमाया। एडीआर की रिपोर्ट में चुनाव आयोग को दी गई पार्टियों की खर्च रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने कुल 57.65 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि कांग्रेस का कुल खर्च 46.19 करोड़ रुपये रहा। वहीं आम आदमी पार्टी का कुल चुनावी खर्च काफी कम, 14.5 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका।

रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने प्रचार पर खास तौर पर सोशल मीडिया को अपना प्रमुख हथियार बनाया। सोशल मीडिया प्रचार पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 5.95 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि भाजपा ने इस मद में महज 5.26 लाख रुपये खर्च किए। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए। पार्टी प्रचार के कुल खर्च में भी कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस ने पार्टी प्रचार पर 40.13 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि भाजपा का यह खर्च 39.14 करोड़ रुपये रहा। आम आदमी पार्टी ने पार्टी प्रचार पर 12.12 करोड़ रुपये खर्च किए।

उम्मीदवारों पर खर्च के मामले में तस्वीर अलग नजर आई। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों पर अपेक्षाकृत कम राशि खर्च की, जबकि भाजपा ने इस मोर्चे पर ज्यादा निवेश किया। एडीआर के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों पर 2.4 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे उसका कुल खर्च 14.5 करोड़ रुपये तक पहुंचा। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार खर्च को मिलाकर कुल 27 करोड़ रुपये का आंकड़ा सामने आया है।

चुनाव में फंड जुटाने के मामले में भाजपा सबसे आगे रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने 88.7 करोड़ रुपये का फंड जुटाया, जबकि कांग्रेस को 64.3 करोड़ रुपये का चंदा मिला। आम आदमी पार्टी को इस दौरान 16.1 करोड़ रुपये का फंड प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर सभी पार्टियों ने चुनाव के दौरान 170.68 करोड़ रुपये का फंड जमा किया। इनमें से ज्यादातर राशि पार्टियों के केंद्रीय मुख्यालय स्तर पर एकत्र की गई थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अब तक नौ पार्टियों ने अपने खर्च का ब्यौरा दिया है, जिनका कुल खर्च 120.3 करोड़ रुपये रहा। इसमें 27 करोड़ रुपये उम्मीदवारों पर खर्च की गई राशि शामिल है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी रही, जिसने 1 करोड़ रुपये से अधिक, यानी करीब 1.8 करोड़ रुपये खर्च किए।

दिलचस्प बात यह है कि 2020 और 2025 दोनों चुनाव लड़ने वाली छह पार्टियों के फंड में इस बार करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा लगभग 170 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं खर्च के रुझान में बड़ा अंतर देखने को मिला। कांग्रेस के खर्च में पिछले चुनाव की तुलना में 222 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि भाजपा ने 2020 के मुकाबले लगभग 25 फीसदी कम खर्च किया। आम आदमी पार्टी के खर्च में भी करीब 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। एडीआर की यह रिपोर्ट एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि क्या ज्यादा पैसा खर्च करना चुनावी जीत की गारंटी है। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का उदाहरण दिखाता है कि आक्रामक प्रचार और सोशल मीडिया पर भारी निवेश के बावजूद जनसमर्थन हासिल करना आसान नहीं होता, जबकि भाजपा ने तुलनात्मक रूप से कम खर्च के साथ बड़ी चुनावी सफलता दर्ज की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से भेंट की

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अहमदाबाद स्थित मजार-ए-कुत्बी में दाऊदी बोहरा समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट दाऊदी बोहरा समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु के अहमदाबाद के वार्षिक दौरे के दौरान हुई।

इस मुलाकात के दौरान सैयदना साहब ने जनकल्याण, सामाजिक समरसता और जिम्मेदार नागरिकता के महत्व पर चर्चा की।

उन्होंने अहमदाबाद के निरंतर हो रहे विकास और शहर की स्थिरता, व्यवस्था एवं नागरिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व की प्रशंसा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 32वें दाई सैयदना कुतबखान कुतुबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी दरगाह पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहर में इस समाज के इतिहास और विरासत की सराहना की।

तत्काल बुकिंग प्रणाली में बदलावः अहमदाबाद मण्डल से चलने वाली और 3 ट्रेनों के लिए OTP प्रमाणीकरण 18 दिसंबर से लागू

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो यात्री द्वारा बुकिंग के समय दिया जाएगा। ओटीपी का सफल सत्यापन होने पर ही टिकट जारी किया जाएगा।

यह OTP-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 18 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित ट्रेनों पर लागू हो जाएगी

1. ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 19316/19315 असारवा-इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 19489 अहमदाबाद– गोरखपुर एक्सप्रेस

निम्नलिखित ट्रेनों में 5 दिसंबर 2025 से OTP-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली प्रारम्भ हो चुकी है।

1. ट्रेन संख्या 12957 साबरमती-नई दिल्ली स्वर्णजयंती राजधानी एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 12297 अहमदाबाद-पुणे दुरन्तो एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 12462 साबरमती-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 12268/12267 हापा–मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस
5. ट्रेन संख्या 12009/12010 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी (01.12.2025 से लागू)

नई प्रणाली कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली सभी तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे बुकिंग के समय वैध मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएँ, ताकि OTP सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे द्वारा सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए के चेक वितरण का गौरवशाली समारोह अहमदाबाद में आयोजित

▸▸ स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए 'सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन' कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ उप मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और शहरी विकास राज्य मंत्री की उपस्थिति

▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात से जो विकास पथ शुरू किया था, उस पर आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ सुनिश्चित करें कि सभी विकास कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके पूर्ण हों : शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने देश के समक्ष यह उदाहरण पेश किया कि दूरदर्शी नेतृत्व और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ यदि धन की कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है

▸▸ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के विरुद्ध राज्य के शहरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ सर्वेक्षण में लीड ली है

▸▸ विकास के कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता दें

▸▸ 2035 में जब हम गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक राज्य के शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए 'सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन' यानी नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहरी निवेश कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे शहरों और महानगरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता सर्वेक्षण में लीड ली है। इतना ही नहीं, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए चार 'आर' रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल और रिकवर पर फोकस किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में शहरी विकास वर्ष की शुरुआत की थी, यह वह दौर था जब देश में शहरीकरण को एक चुनौती माना जाता था। उन्होंने हमारी विरासत के अनुरूप शहरी विकास मॉडल विकसित करने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की मजबूत नींव रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में शहरी विकास वर्ष के जरिए इसका श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है कि, यदि दूरदर्शी नेतृत्व हो और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ धन की कोई कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास वर्ष 2005 की दो दशकों की सफलता के चलते मॉडर्न अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी आधुनिक शहरी परिवर्तन में बड़ा बदलाव आया है। इस परिवर्तन को और अधिक गति देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वस्पर्शी, सर्वपोषक और सर्वसमावेशी नगरों के विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया है।

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में बुधवार को अहमदाबाद आयोजित कार्यक्रम में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए एक साथ, एक ही मंच से कुल 2800 करोड़ रुपए राशि के चेक वितरित किए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई और राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला की उपस्थिति में राज्य की 8 महानगर पालिकाओं को कुल 2132 करोड़ रुपए तथा नवगठित 9 महानगर पालिकाओं को 40-40 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 360 करोड़ रुपए की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए दी।

इसके अलावा, राज्य की 152 नगर पालिकाओं को कुल 308 करोड़ रुपए सहित कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ऐसा वित्तीय प्रबंधन किया है, जिसमें नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के आयोजन में धन की कोई कमी रहे। अब नगर पालिकाओं को लोगों के विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन का उपयोग करने की क्षमता बढ़ानी होगी।

उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता देने का प्रेरक सुझाव देते हुए कहा कि स्वच्छता सभी का सहज स्वभाव बन गया है, ऐसे में नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं को चाहिए कि वे इस दिशा में और अधिक पहल करने का दायित्व निभाएं।

श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने वाले राज्य के 6 शहरों का उल्लेख किया और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सभी शहरों को लीड लेने और प्रत्येक वार्ड में कचरे का 100 फीसदी पृथक्करण करने के साथ ही नगर पालिकाओं में बिजली बिल की बचत के लिए हरित एवं स्वच्छ सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण का रोडमैप 'अर्निंग वेल, लिविंग वेल' के संकल्प के साथ तैयार किया गया है। 2047 के विकसित भारत से पहले, जब 2035 में गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, तब तक हमारे शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है।

उन्होंने महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मोबाइल गवर्नेंस का दायरा बढ़ाते हुए सभी शहरों में टैक्स कलेक्शन और बिजली बिल सहित सभी बिलों के भुगतान के लिए यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस मौके पर शहरी विकास के लिए एक ही स्थल से राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को चेक वितरित करने के इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं और मुश्किलों के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्व और शहरी विकास के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयासरत रहते हुए जनकल्याण के अनेक कार्य पूर्ण कराए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के अनेक शहरों ने आगे बढ़कर देश में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दशक पहले की सरकारों के दौर में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में निरंतर मुश्किलों के बीच जीना पड़ता था। लेकिन, श्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री शासन की कमान संभालने के बाद गुजरात के शहर और जिले लगातार विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़े हैं और आज पूरा देश विकास की इस तेज गति को देख रहा है। उन्होंने उच्च स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के साथ नगरों के सतत विकास की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य की 9 नगर पालिकाएं अब महानगर पालिका बन गई हैं। उन्होंने धोलेरा और गिफ्ट सिटी का उदाहरण देते हुए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया।

शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात के विकास के लिए अनेक नए आयाम गढ़े और योजनाएं लागू कीं। उन्होंने ज्योतिग्राम योजना, शाला प्रवेशोत्सव और वाइब्रेंट गुजरात जैसी योजनाओं और अभियानों के अलावा आदिवासी विकास के लिए अलग से बजट आवंटन तथा 2009-10 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की थी।

श्री देसाई ने कहा कि उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास विभाग का बजट 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। शहरों में सड़क, सैनिटेशन, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर सहित शहरी विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए शहरी विकास विभाग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने सभी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के पदाधिकारियों से सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर बल दिया।

शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने स्वागत भाषण में कहा कि राज्य सरकार महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सदैव कटिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास की लगातार चिंता की थी। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी शहरी विकास विभाग के बजट में लगातार बढ़ोतरी कर लोगों की सुख-सुविधा बढ़ाने और अनेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।

इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की झलक दिखाने वाली लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में विधानसभा के उप मुख्य सचेतक श्री जगदीशभाई मकवाणा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, स्थानीय विधायक, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज श्रीमती रेम्या मोहन, म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की अपर आयुक्त श्रीमती वीमा पटेल सहित राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

गुजरात में भागकर शादी पर सख्ती, माता-पिता को नोटिस अनिवार्य, पंजीकरण में नए नियम लागू होने की तैयारी

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात सरकार अब भागकर शादी करने वाले जोड़ों के लिए कानून में बड़े बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, अब किसी भी शादी का पंजीकरण कराने से पहले जोड़े के माता-पिता को नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। इस नोटिस के जवाब में अभिभावकों को 30 दिन का समय मिलेगा और इस प्रक्रिया के पूरा होने तक शादी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम उन मामलों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है, जिनमें जोड़े बिना परिवार की जानकारी के भागकर शादी करते हैं और पंजीकरण करा लेते हैं। सरकार के सूत्रों के अनुसार, यह संशोधन शादी पंजीकरण अधिनियम में ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। राज्य के कानून मंत्री और विशेषज्ञ आज शाम इस नए कानून का मसौदा तैयार करेंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद ही इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा।

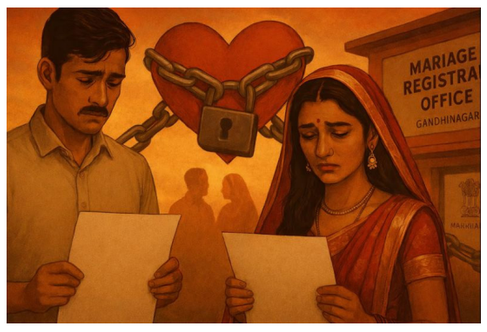

नए नियमों के अनुसार, अब से शादी पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर रजिस्ट्रार कार्यालय सबसे पहले लड़की और लड़के के माता-पिता को नोटिस भेजेगा। नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे माता-पिता को बिना जानकारी के होने वाली शादियों पर रोक लग सकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

साथ ही, पंजीकरण के स्थान को लेकर भी सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। अब जोड़े किसी भी जिले में जाकर शादी पंजीकरण नहीं करा पाएंगे। नए नियम के अनुसार, लड़की के आधार कार्ड में दर्ज पते वाले क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में ही शादी पंजीकरण अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि परिवार को बिना जानकारी के गुप्त रूप से शादी करने का मौका नहीं मिलेगा।

पाटीदार समाज और अन्य सामाजिक संगठनों ने लंबे समय से इस सुधार की मांग की थी। उनका कहना था कि बेटियों को भगा ले जाने के मामलों में मौजूदा कानूनी खामियों का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे परिवार टूट रहे थे। नए नियमों से यह सामाजिक बुराई कम होगी और परिवार संरचना सुरक्षित रहेगी।

इस पूरे मुद्दे में मीडिया की भूमिका भी अहम रही। पाटीदार नेताओं वरुण पटेल और बांभणिया ने मीडिया का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 2023 में जब इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही थी, तब एबीपी अस्मिता चैनल ने सबसे पहले इस मामले को उठाया और अभियान चलाया। मीडिया के प्रयासों के कारण ही सरकार ने अब इस दिशा में कदम उठाने की ठानी है।

सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियमों के लागू होने के बाद गुजरात में सामाजिक सुरक्षा के स्तर में सुधार होगा। माता-पिता को विवाह से पूर्व सूचना देने का प्रावधान न केवल पारिवारिक संरचना को मजबूत करेगा, बल्कि जोड़े और समाज में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह कदम उन युवा जोड़ों को चेतावनी देगा, जो बिना परिवार की जानकारी के शादी करने का सोचते हैं।

इस बदलाव से यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि राज्य सरकार सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक संरचना की रक्षा के लिए गंभीर है। जब नए नियम लागू होंगे, तो शादी पंजीकरण के सभी मामलों में माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। इस पहल को लेकर समाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और इसे ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

गुजरात में भागकर शादी करने पर यह सख्त नियम आने के बाद स्थानीय प्रशासन और पंजीकरण कार्यालयों को भी नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। अब प्रत्येक आवेदन का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाएगा, और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह न केवल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह परिवारों और युवाओं के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा।

इस तरह, गुजरात सरकार अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के तहत भागकर शादी करने वाले जोड़ों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और इसके लागू होने के बाद यह सुनिश्चित होगा कि शादी पंजीकरण पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो।

'होमबाउंड' ऑस्कर की राह पर: भारतीय सिनेमा का अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरव

(जीएनएस)। मुंबई। भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट कृति 'होमबाउंड' ने एक बार फिर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। फिल्म निर्देशक नीरज घेवान की यह फिल्म 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर) की 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। इस उपलब्धि के साथ 'होमबाउंड' दुनिया भर की उन चुनिंदा 15 फिल्मों में शामिल हो गई है, जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की मुख्य रेस में बनी हैं। हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेसी इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं, जबकि फिल्म का निर्माण करण जौहर और आदर पूनावाला ने किया है।

ऑस्कर की इस शॉर्टलिस्ट में भारत की 'होमबाउंड' का मुकाबला अर्जेंटीना की 'बेलेन', ब्राजील की 'द सीक्रेट एजेंट', जर्मनी की 'साउंड ऑफ फॉलिंग' और 11 अन्य अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से है। फिल्म की शॉर्टलिस्टिंग भारतीय सिनेमा के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता और उसकी कलात्मक क्षमता को दर्शाती है।

फिल्म की कहानी दो ग्रामीण दोस्तों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। एक मुस्लिम और दूसरा दलित, दोनों समाज में सम्मान और पहचान पाने के लिए पुलिस की नौकरी का सपना देखते हैं। यह फिल्म समाज में गहरे जातिगत और धार्मिक भेदभाव के मुद्दों को बेहद संवेदनशील और सटीक ढंग से पेश करती है। कहानी पत्रकार बशारत पीर के लेख 'टेकिंग अमृत होम' से प्रेरित है। फिल्म में ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

अकादमी ने अन्य 11 कैटेगरी में भी शॉर्टलिस्टिंग की घोषणा की है। 98वें ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन 22 जनवरी, 2026 को घोषित किए जाएंगे, जबकि पुरस्कार वितरण समारोह 15 मार्च, 2026 को डॉल्बी थिएटर, हॉलीवुड में आयोजित होगा। हर कैटेगरी में पांच- पांच नॉमिनी होंगे, जबकि बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में दस नॉमिनी शामिल होंगे। इस समारोह का सीधा प्रसारण दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में होगा।

'होमबाउंड' की अंतरराष्ट्रीय शॉर्टलिस्टिंग न केवल भारतीय सिनेमा की गुणवत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उजागर करने का माध्यम भी बन रही है। फिल्म की कहानी, पात्रों की सजीव अभिव्यक्ति और सामाजिक संदेश इसे एक वैश्विक मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह उपलब्धि भारतीय फिल्म उद्योग के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी है, और दर्शकों में फिल्म के प्रति उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ा रही है।

गुजरात सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगाया बड़ा प्रतिबंध, रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन हुईं पूरी तरह बैन

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात में युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। गृह विभाग ने पूरे राज्य में रोलिंग पेपर, 'गो गो स्मोकिंग कोन' और 'परफेक्ट रोल' जैसी वस्तुओं की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन वस्तुओं की बिक्री करना कानूनी अपराध माना जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ये उत्पाद न केवल पान पार्लर, चाय की दुकानों और किराने की दुकानों में उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इन्हें बेचना या उपलब्ध कराना अपराध होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कुछ समय में गुजरात में युवाओं और नाबालिगों में नशे की लत तेजी से बढ़ रही थी। विशेष रूप से 'एबीपी अस्मिता' द्वारा चलाए गए अभियान में यह उजागर

हुआ कि 'गो गो पेपर' और अन्य स्मोकिंग कोन खुलेआम बाजार में बिक रहे थे और इनका इस्तेमाल चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए किया जा रहा था। अभियान में यह भी सामने आया कि इन रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटैशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल रंग, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जो लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) और 163(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस कदम को अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने सकारात्मक रूप से देखा है। लोग मानते हैं कि यह कदम युवाओं को आसानी से मिलने वाली नशे की सामग्री से दूर रखने में मदद करेगा और समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रतिबंध से न केवल नशे के दुष्प्रभावों से बचाव होगा, बल्कि यह युवाओं के सुरक्षित भविष्य और स्वास्थ्य की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।

राज्य सरकार का कहना है कि युवाओं की सुरक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। इस कदम के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नशे की सामग्री आसानी से उपलब्ध न हो और युवा इस खतरनाक प्रवृत्ति से दूर रहें। सरकारी अधिकारियों और पुलिस विभाग ने भी इस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं और राज्य भर में इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

इस ऐतिहासिक निर्णय से यह संदेश गया है कि गुजरात सरकार युवाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए गंभीर है। समाज में जागरूकता फैलाने और नशे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए यह कदम भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा।

सूरत में केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर, मजदूर घायल

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत जिले के पलसाना इलाके में बुधवार को माखीगा गांव स्थित श्री बालाजी केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री परिसर के बाहर भी लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दस से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। बारडोली, कडोदरा, कामरेज, सचिन सहित आसपास के क्षेत्रों की फायर टीमें भी आग बुझाने में लगी हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मी फोम का छिड़काव कर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पानी की बौछारों से आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग तेजी से फैल रही है और घटनास्थल पर पलसाना पुलिस का काफिला भी मौजूद है। आग की चपेट में एक मजदूर घायल हुआ है, जिसे तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

स्थानीय प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। आग लगने के कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन फैक्ट्री में बने केमिकल की वजह से आग तेजी से फैल रही है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आग पर नियंत्रण पाने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इस हादसे ने इलाके में अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया है। फायर विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि आग की जांच और नुकसान का आकलन किए जाने के बाद ही आग लगने की असली वजह का पता चल पाएगा। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे फिलहाल फैक्ट्री के आसपास न आएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इस घटना से पलसाना और आसपास के इलाके में सुरक्षा और सतर्कता को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है, और फायर ब्रिगेड के लगातार प्रयासों के बावजूद आग ने अभी भी काफी हिस्सों में अपना प्रकोप बरकरार रखा हुआ है।

चांदी, चांदी-मिनी और चांदी-माइक्रो वायदा ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचे: सोना वायदा में 173 रुपये की नरमी

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 184701.61 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 45125.1 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 139566.38 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 33071 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2479.13 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 38578.72 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 135079 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 135249 रुपये और नीचे में 133373 रुपये पर पहुंचकर, 134409 रुपये के पिछले बंद के सामने 173 रुपये या 0.13 फीसदी गिरकर 134236 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 49 रुपये या 0.05 फीसदी की तेजी के संग 107578 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 17 रुपये या 0.13 फीसदी की तेजी के संग 13466 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132600 रुपये के भाव पर खूलकर, 133490 रुपये के दिन के उच्च और 132060 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 55 रुपये या 0.04 फीसदी की तेजी के संग 132682 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 133419 रुपये के भाव पर खूलकर, 133784 रुपये के दिन के उच्च और 132358 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132949 रुपये के पिछले बंद के सामने 95 रुपये या 0.07 फीसदी की तेजी के संग 133044 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 199201 रुपये के भाव पर खूलकर, 206111 रुपये के ऑल टाइम हाई और 199201 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 197755 रुपये के पिछले बंद के सामने 6920 रुपये या 3.5 फीसदी की बढ़त के साथ 204675 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 6750 रुपये या 3.4 फीसदी की मजबूती के साथ 205150 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 6837 रुपये

क्रूड ऑयल वायदा 52 रुपये तेजः कमोडिटी वायदाओं में 45125.1 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 139566.38 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 38578.72 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 33071 पॉइंट के स्तर पर

या 3.45 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 205200 रुपये प्रति किलो पर आ गया। चांदी-मिनी फरवरी वायदा 206454 रुपये और चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 206390 रुपये के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचा था। मेटल वर्ग में 3917.94 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 5.1 रुपये या 0.46 फीसदी बढ़कर 1111 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 40 पैसे या 0.13 फीसदी बढ़कर 303.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.1 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 281.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 85 पैसे या 0.47 फीसदी टूटकर 180.3 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2622.03 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5095 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5131 रुपये और नीचे में 5030 रुपये पर पहुंचकर, 52 रुपये या 1.03 फीसदी बढ़कर 5123 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 55 रुपये या 1.09 फीसदी की तेजी के संग 5124 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 359 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 366.2 रुपये और नीचे में 354.8 रुपये पर पहुंचकर, 356 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.5 रुपये या 0.98 फीसदी बढ़कर 359.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 3.6 रुपये या 1.01 फीसदी की तेजी के संग 359.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 945.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 19.7 रुपये या 2.08 फीसदी की बढ़त के साथ 965.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 18213.50 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 20365.23 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3058.01 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 352.64 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 21.83 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 485.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 992.80 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1618.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 16905 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 77157 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 21981 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 346149 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 36990 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17273 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39352 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 112331 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 26254 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 40213 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 33079 पॉइंट पर खूलकर, 33215 के उच्च और 33000 के नीचले स्तर को छूकर, 253 पॉइंट बढ़कर 33071 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 31.6 रुपये की बढ़त के साथ 203 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.55 रुपये की बढ़त के साथ 13.1 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 34.5 रुपये की गिरावट के साथ 1826 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 205000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3283.5 रुपये की बढ़त के साथ 5801.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.36 रुपये की बढ़त के साथ 12.4 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 15 पैसे के सुधार के साथ 2.01 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 40.2 रुपये की गिरावट के साथ 167.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.95 रुपये की गिरावट के साथ 13.8 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 128000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 11.5 रुपये की गिरावट के साथ 315 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2860 रुपये की गिरावट के साथ 3580 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.89 रुपये की गिरावट के साथ 10.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.04 रुपये की बढ़त के साथ 3.35 रुपये हुआ।

अमरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, खेत में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन युवकों की मौके पर मौत

(जीएनएस)। अमरेली। गुजरात के अमरेली जिले की बगसरा तहसील में बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हडाला गांव के पास तेज गति से जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और खेत में खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चार लोगों में से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान जूनागढ़ निवासी विकास सावलिया (38), राजकोट जिले की धोराजी तहसील के जालणसर गांव निवासी मंथन सावलिया (26) और धर्मेश सावलिया (29) के रूप में हुई है। वहीं, नीरजभाई मकवाणा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक और घायल सभी एक ही

कार में सवार होकर यात्रा कर रहे थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकास, मंथन, धर्मेश और नीरज बुधवार सुबह कार से जूनागढ़ की ओर जा रहे थे। अमरेली जिले की बगसरा तहसील में हडाला गांव के पास डेरी पीपळिया गांव की पटिया के समीप कार तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान चालक विकास सावलिया का वाहन पर से नियंत्रण हट गया। कार सीधे सड़क से नीचे उतरती चली गई और खेत में खड़े एक पेड़ से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद कार में सवार विकास, मंथन और धर्मेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नीरज की हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी। सूचना मिलते ही अमरेली फायर ब्रिगेड की टीम फायर ऑफिसर एच.पी. सरतेजा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। बगसरा पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

घायल नीरज को पहले बगसरा और फिर गंभीर हालत को देखते हुए अमरेली अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बताया जा रहा है कि सभी चारों युवक अमरेली के वडिया क्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे और वापस जाते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया। एक साथ तीन युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया है। इलाके में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

अहमदाबाद में थैलेसीमिया जागरूकता रैली, विवाह और परिवार नियोजन से पहले जांच पर जोर

(जीएनएस)। अहमदाबाद। रोटरी क्लब अहमदाबाद एयरपोर्ट द्वारा आयोजित थैलेसीमिया जागरूकता रैली ने शहर में स्वास्थ्य और भविष्य पीढ़ियों की सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। रैली में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3055 के गवर्नर निगम चौधरी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने विवाह से पूर्व और परिवार नियोजन से पहले थैलेसीमिया जांच कराने की अनिवार्यता पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे न केवल संभावित माता-पिता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इस गंभीर रक्त रोग से बचाया जा सकता है।

इस अवसर पर क्लब ने गंभीर थैलेसीमिया रोगियों के लिए 'रोटरी थैला पंप बैंक' का उद्घाटन भी किया। यह पंप उन रोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्हें बार-बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। बार-बार रक्त चढ़ाने से शरीर में लौह (आयरन) की अधिकता हो सकती है, जिसे इस पंप

की मदद से नियंत्रित किया जाएगा और रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यक्रम में नए सदस्यों का स्वागत किया गया और विभिन्न गतिविधियों में योगदान देने वाले सदस्यों को पिन लगाकर सम्मानित किया गया। थैलेसीमिया कमेटी के चेयरमैन डॉ. अनिल खत्री ने कहा कि जागरूकता और उपचार में योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना उनका कर्तव्य है, ताकि समाज में थैलेसीमिया के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बनी रहे।

रैली का आयोजन वाडज स्थित रेडक्रॉस भवन में किया गया। रोटरी क्लब अहमदाबाद एयरपोर्ट के अध्यक्ष सत्यनारायण समदानी ने कहा कि यह रैली केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक स्थायी संकल्प है। उनका उद्देश्य है कि आज की जागरूकता को आने वाले कल की रोकथाम में बदला जाए और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से प्रभावित परिवारों की संख्या को न्यूनतम किया जा सके।

इस जागरूकता कार्यक्रम में आम नागरिकों के अलावा स्वास्थ्यकर्मी, रोटरी सदस्य और छात्रों ने भी भाग लिया। रैली में मार्गदर्शन और प्रचार के माध्यम से लोगों को थैलेसीमिया के लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपायों के बारे में बताया गया। आयोजकों ने जोर देकर कहा कि समय रहते जांच कराना और सावधानी अपनाना ही इस रोग से बचने का सबसे कारगर तरीका है।